**अध्यक्ष महोदय :** यह तेजी भी इस में उधर से आयी जिस दिन आसाम का इन्होंने सुना । तो इन्होंने कहा कि हम भी मार्का मारेंगे कोई ।

---

**13.06 hrs.**

## MATTERS UNDER RULE 377

### (i) Reported publication of a new edition of the 'Indian Express' from Cochin in violation of Government Policy re. Newsprint

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Sir, under rule 377, I wish to invite the attention of the House to a grave matter, a policy departure by the Government of India and the Ministry of Information and Broadcasting on the question of diffusion and delinking of the press, which has been repeatedly reiterated in both the Houses. I am reliably informed that the *Indian Express* chain of newspapers, which has already 22 newspapers, which is very well-known for its notorious mismanagement, illtreatment of journalists and various other fraudulent practices, has been allowed to start a new edition of *Indian Express* from Cochin from today. I am told it has come out today or is coming out sometime during the week. When there is acute shortage of newsprint and foreign exchange is hardly available for importing it, I want to know how this newspaper is being given newsprint to start a new edition, when language newspapers are closing down their editions and journalists are being retrenched. How was this paper permitted to start a new edition? Is it not a policy departure? Where did they get the newsprint for this new edition? I would request you to direct the Minister to make a statement about it at the earliest opportunity.

MR. SPEAKER: This question has been raised by many others also—Shri Amrit Nahata, Shri Shashi Bhushan, Shri Chandrakar and others. I am not allowing all. I allowed one. I had a lot of hesitation in my mind when allowing it. Mr. Unnikrishnan wrote to the office that it is a violation of law. If there is any violation, the Minister will explain it.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (ग्वालियार) : अध्यक्ष महोदय, अगर वायलेशन का सवाल है तो दिल्ली का एक पेपर अपने पेज बढ़ाता जा रहा है जिस का नाम "पैट्रियट" है । मंत्री महोदय यह भी बता दें कि वह वायलेशन कर रहा है कि नहीं ।

### (ii) Reported Kidnapping of a Worker at Modi Nagar

**श्री हुकम चन्द कछवाय** (मुरेना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं ।

मोदीनगर में मजदूरों का जो आन्दोलन चल रहा है, उस के सम्बन्ध में कल काफी मजदूर रेल द्वारा वहां से दिल्ली आना चाहते थे, लेकिन मोदी मालिक ने स्टेशन मास्टर को टेलीफोन कर दिया कि किसी कर्मचारी को रेल का टिकट न दिया जाये, ताकि वे लोग दिल्ली न आ पाय । इस तरह उन लोगों को वहां रोक लिया गया मैं बताना चाहता हूं कि उन लोगों का आन्दोलन क्यों चल रहा है । मोदी मालिकों ने वहां की यूनियन के लीडर, सुभाष शर्मा, को पिस्तौल और चाकू दिखा कर रात को उस के घर से गायब करने की कोशिश की और उस को जान से मारने का प्रयास किया । मोदी मालिकों के द्वारा वहां हर साल चार पांच मजदूरों का मर्डर किया जाता है, लेकिन उन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है । 21 नवम्बर से वहां पर मजदूरों का शान्तिमय आन्दोलन चल रहा है, जिस में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हुई है । इसके बावजूद वहां परसों रात को बारह बजे दफ़ा 144 लगा दी गयी । कर्मचारियों ने एक गांव में जा कर अपनी सभा की । पुलिस ने उन को घेर लिया और उन को मारा-पीटा । पुलिस इन्स्पैक्टर सिंगर ने लोगों को गोली से मारने की धमकी दी । अनेक महिलाओं को मारा-पीटा गया । एक

[श्री हुकम चन्द कछवाय]

महिला को घसीटा गया, जिस के फटे हुए और खून से सने हुए कपड़े में सुबूत के तौर पर सदन को दिखाना चाहता हूं ।

इन घटनाओं के बारे में कोई समाचार किसी भी पत्र में नहीं आता है । वहां पन्त नाम के एक पत्रकार हैं, जिन के पास सभी समाचार पत्रों की एजेंसी है, लेकिन वह किसी भी समाचार पत्र को इस बारे में समाचार नहीं भेजते हैं । वह मोदी मालिकों की सर्विस करते हैं । इस कारण इन घटनाओं के बारे में कोई खबर किसी भी समाचारपत्र में नहीं छपती है ।

चूंकि उन लोगों को रेल का टिकट नहीं दिया गया, इस लिए 900 व्यक्ति कल मोदीनगर से पैदल चल कर दिल्ली आये हैं । मैं खुद छः मील पैदल चला हूं । मेरा निवेदन है कि आप सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देने के लिये कहें । सरकार की ओर से कहा जा सकता है कि यह विषय उस के अन्तर्गत नहीं आता है । लेकिन मैं यह प्रश्न इस लिए उठा रहा हूं कि रेलवे की ओर से, जो केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है, उन लोगों को टिकट नहीं दिये गये ।

वहां स्थिति यह है कि पुलिस सब कर्मचारियों को धौंस देती है और उन को जान से मारने की धमकियां देती है । पुलिस इन्स्पैक्टर सिंगर को अलग से पांच हजार रुपये की इनकम मोदी मालिकों से होती है ।

**अध्यक्ष महोय** : मोदीनगर तो यू०पी० में है ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि क्या कोई मिल मालिक रेलवे को कह सकते हैं कि उन के मजदूरों को दिल्ली आने के टिकट लिए न दिये जायें ? क्या रेलें मोदी के इशारे पर चलती हैं या भारत सरकार द्वारा चलाई जाती हैं ? आप इस बारे में मंत्री महोदय को पता लगाना के लिये कहें ।

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : मजदूरों की शान्तिमय हड़ताल चल रही थी, जिस में कोई गड़बड़ नहीं हुई । वहां जो दफा 144 लगाई गई, उस का ऐलान मोदी मालिकों ने अपने नौकरों के द्वारा, अपनी जीप पर अपना माइक लगवा कर रात के बारह बजे करवाया । यह कितने आश्चर्य की बात है कि दफा 144 मालिकों के द्वारा लगाई जाती है, सरकारी अधिकारियों के द्वारा नहीं ।

मोदीनगर में नगरपालिका बनने की सब प्रकार की पात्रता है, लेकिन मोदी मालिक उस को नगरपालिका नहीं बनने देते हैं । उन्होंने वहां के प्रशासन को खरीद रखा है । आप सरकार को कहें कि वह इस बारे में पूरी जांच कर के यहां वक्तव्य दे कि लोगों को रेल के टिकट नहीं दिये गये । उन लोगों को वहां पैदल आना पड़ा । वे लोग रात भर चल कर रात के बारह बजे यहां पहुंचे ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): So far as the dispute in Indian Airlines is concerned, even though the negotiations are going on, there is a deadlock now. Both the management and the workers do not seem to want to change their stand. The result is that hundreds of workers, not to speak of passengers, are put to a lot of difficulty. I want the Minister to make a statement on this. They are making statements on all subjects except this.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : अध्यक्ष महोदय, हम ने इस बारे मे काल-एटेन्शन नोटिस दिया हुआ है। इंडियन एयर-लाइन्ज और उस के कर्मचारीयों के बीच होने वाली बातचीत में डेडलाक हो गया है यात्रियों से अपना खादा साथ लाने के लिए कहा जा रहा है। यात्रियों के लिए भोजन बन्द कर दिया गया है। उन्हे यह भी कहा गया है कि वे अपना सामान न लायें, क्योंकि सामान उठाने का इन्तजाम नही है।

MR. SPEAKER: I will be conveying this to the Minister.

**13.15 hrs.**

*The Lok Sabha adjourned for Lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock.*

---

*The Lok Sabha re-assembled after Lunch at eighteen minutes past Fourteen of the Clock.*

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

## BURN COMPANY AND INDIAN STANDARD WAGON COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Damodar Pandey to continue his speech.

**श्री दामोदर पांडे** (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कल कह रहा था इस तरह के अधिग्रहण जब किए जाते हैं, कारखानों को लिया जाता है तो एक मंशा होती है उस के पीछे कि हम क्यों उस को लेना चाहते हैं। मंशा यह होती है कि उस को अच्छे ढंग से चलाया जाय, मजदूरों की मुश्किलें हैं, उन की जो तकलीफें हैं उन को दूर किया जाय और देश की ऐकोनामी में उस कारखाने का जो उचित योगदान होना चाहिए था उस के लिए उस को सक्षम बनाया जाय और इसी नीयत से इस तरह के कारखाने लिए जाते हैं। लेकिन इस सिलसिले में जो कार्यवाही अभी तक की गई है उस से बड़ा असंतोष, बड़ा डिसएप्वाइंटमेंट होता है। आज से डेढ़ साल पहले जब इंडियन आयरन ऐंड स्टील कम्पनी को टेक ओवर किया गया था तो मजदूरों में एक खुशी की लहर दौड़ी थी। सभी लोगों को यह विश्वास था कि जब इस का सरकारीकरण कर लिया गया है, सरकार ने इस के इंतजाम को अपने साथ ले लिया है तो इस में बाजाठता सुधार होगा। लेकिन सुधार तो इतना ही हुआ जैसा कि कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि उन्हीं अफसरों में से एक अफसर को जो सारी बंग्लिंग के लिए जिम्मेदार थे, जिन की बजह से सारे कार-खाने चौपट हो गए थे उन्हीं में से एक अफसर को सिर्फ बोर्ड बदल कर उस का कस्टोडियन बना दिया गया। आज डेढ़ साल के बाद भी ठेकेदारी प्रथा वहां कायम है। मजदूरों की हालत में भी कुछ विशेष सुधार नहीं हुआ है जिस सुधार की कि हम लोग अपेक्षा कर थे। तो क्या इस तरह से टेक ओवर करने का कोई जायज कारण हो सकता था ? अगर यही करना था कि उन्हीं अफसरों में से एक को सिर्फ उस का मालिक बना कर बैठा देना था और उस की अब यह अकड़ और हो जाय कि अब तो वह सरकारी अफसर हो गया, अब तो कोई भी उस के ऊपर या नीचे उसे देखने वाला रहा नहीं तो इस तरह के अधिग्रहण का क्या फायदा है ? आखिर क्यों हम अधि-ग्रहण करना चाहते है ? जो कुछ भी हमारे मन में बात है कि हम चाहते हैं कि यह कारखाना बढ़ोत्तरी से चले, हम जिस तरह, की अपेक्षा रखते थे कि इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी की हालत में सुधार हो उस में अच्छा प्रोडक्शन हो, वह न हो कर के उस की दिन व दिन हालत और खराब होती जाती है। उस पर देश की एकोनामी बहुत हद तक निर्भर करती है। उस में जो हम सुधार की अपेक्षा रखते थे वह नजर नहीं आ रहा है और खास कर के हमारे जैसे मजदूर वर्ग